



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

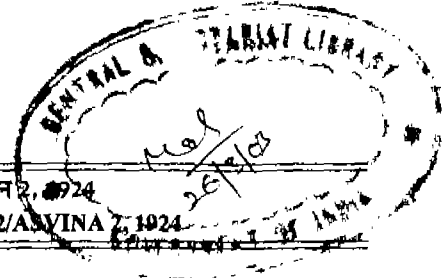
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 839]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2002/आश्विन 2, 1924

No. 839]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2002/ASHWINA 2, 1924



भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 24 सितम्बर, 2002

का.आ. 1030(अ).— यतः माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 13 मार्च 2001 को संसद में घोषणा की थी, कि "स्टाक एक्सचेंजों का निगमीकरण जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन, तथा व्यापारिक सवस्यता का एक वूसरे से पृथक्करण हो जायेगा। तदनुसार प्रशासनिक कवम उठाये जायेंगे और विधायी परिवर्तन, यदि अपेक्षित हों, प्रस्तावित किये जायेंगे।" उपर्युक्त, नीति घोषणा के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "भाप्रविबो" के रूप में निर्दिष्ट) ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ समय-समय पर अपरस्पर्ीकरण के विषय पर चर्चा की थी और

यतः भाप्रविबो बोर्ड ने 28 दिसंबर 2001 को आयोजित अपनी बैठक में, स्टॉक एक्सचेंजों के अपरस्पर्ीकरण के विषय पर चर्चा की और विनिश्चय किया कि अब से कोई दलाल सवस्य एक्सचेंज का पवाधिकारी नहीं होगा, अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि का पद धारण करना, और एक्सचेंजों के निगमीकरण और अपरस्पर्ीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के अन्य प्रशासनिक तथा विधिक तौरतरीके निर्धारित किये जा रहे हैं; और

यतः तत्पश्चात्, भाप्रविबो ने सभी एक्सचेंजों जिनमें द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन लि. (इसमें इसके पश्चात् "सीएसई" के रूप में निर्दिष्ट) भी सम्मिलित है को तारीख 10 जनवरी, 2002 के परिपत्र सं. एसएमडी/पॉलिसी/सीआइआर-2/2002 द्वारा, उनके नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि, को उक्त आदेश की तारीख से दो मास के भीतर उपयुक्त रूप से संशोधित करते हुए भाप्रविबो बोर्ड के विनिश्चय को कार्यान्वित करने का निदेश दिया; और

यतः भाप्रविबो ने तारीख 19 मार्च 2002 के पत्र सं. एसएमडी /सीएसई/एडीएमएन/4536/02 द्वारा सीएसई को पुष्टि करने की सलाह दी कि क्या उन्होंने भाप्रविबो के 10 जनवरी 2002 के निदेश, भाप्रविबो के परिपत्र सं. 2 द्वारा जारी, का अनुपालन किया था, जिसके द्वारा कोई दलाल सदस्य निदेश की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने के लिए अनुज्ञात नहीं था और सीएसई को यह पुष्टि करने की भी सलाह दी गयी कि क्या उन्होंने भाप्रविबो बोर्ड द्वारा लिये गये उपर्युक्त विनिश्चय को और इस संबंध में सरकार के नीति-विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए नियमों, संगम अनुच्छेद इत्यादि, को उपयुक्त रूप से संशोधित कर लिया था ; और

यतः ऊपर उल्लिखित पत्र तथा तारीख 10 जनवरी 2002 के परिपत्र के उत्तर में, सीएसई ने अपने तारीख 19.3.2002 के पत्र द्वारा सूचित किया कि उक्त निदेश को आचरण के आदर्श नियमों के कार्यान्वयन के पश्चात् सम्मिलित किया जायेगा और यह कि एक्सचेंज के संगम-ज्ञापन तथा संगम-अनुच्छेद में समुचित परिवर्तन समिति / भाप्रविबो / शेयरधारकों के साधारण निकाय द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात् किये जायेंगे, कि प्रक्रिया आरंभ हो गयी है और

यतः अधिकांश स्टॉक एक्सचेंजों ने 10.1.2002 के आदेश को प्रभावी करने के लिए अपने नियमों / संगम अनुच्छेदों को संशोधित किया है, और उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संगम अनुच्छेद को संशोधित करने में सीएसई असफल रहा है, भाप्रविबो की राय है कि विनिधानकर्ताओं और पूँजी बाजारों के हित में, लोक हित में भी, संगम अनुच्छेद को संशोधित करना आवश्यक तथा समीचीन है, इस आदेश में उपदर्शित रीति में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कारणों से अर्थात् :

- (i) स्टॉक एक्सचेंजों के शीघ्र निगमीकरण के लिए जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन, तथा व्यापारिक सदस्यता का एक दूसरे से पृथक्करण स्टॉक बाजारों में संस्थागत प्रणालीतंत्र तथा व्यापारिक पद्धतियों में सुधार लाने के लिए हो जायेगा ।
- (ii) इसके अलावा, बोर्ड देश के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्ड की संरचना संबंधी नियमों, विनियमों तथा उप-विधियों में एकरूपता बनाये रखने के लिए इसे वांछनीय पाता है ।

अब, इसलिये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, उक्त अधिनियम की धारा 29क के अधीन जारी इसकी तारीख 3 जुलाई 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. / 573(अ) के अधीन भाप्रविबो द्वारा बोर्ड को प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीएसई के संगम अनुच्छेद में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :-

1. अनुच्छेद 82ड खंड (i) में,

- क) शब्दों "सदस्यों" के पूर्व दिए हुए शब्द "निर्वाचित" को हटा दिया जायेगा।
- ख) शब्द "समिति" के पश्चात् और शब्दों "दस दिनों के भीतर" के पूर्व दिए हुए शब्दों "अनुच्छेद 81 के खंड (क) के अधीन" को हटा दिया जायेगा।
- ग) परंतुक में, शब्द "कोई" के पश्चात् और शब्द "सदस्य" के पूर्व दिए हुए शब्द "निर्वाचित" को हटा दिया जायेगा।
- घ) विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक परिवर्धित किया जायेगा :

"परंतु यह और कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का पदाधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोषाध्यक्ष नहीं होगा।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/18591/02]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 24th September, 2002

S.O. 1030(E).— **Whereas** the Hon'ble Finance Minister had announced in the Parliament on March 13, 2001, that "corporatisation of stock exchanges by which ownership, management, and trading membership would be segregated from each other. Administrative steps will be taken and legislative changes, if required, will be proposed accordingly." In accordance with the above, policy announcement, The Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI") had discussed the issue of demutualization with the stock exchanges from time to time and

Whereas SEBI Board in its meeting held on December 28, 2001, discussed the issue of demutualization of the stock exchanges and decided that henceforth no

broker member shall be an office bearer of an exchange that is hold the position of the President, Vice-President, Treasurer etc., and the other administrative and legal modalities for corporatisation and demutualization of exchanges of the stock exchanges are being worked out; and

Whereas subsequently, SEBI directed all the exchanges including The Calcutta Stock Exchange Association Ltd (hereinafter referred to as "CSE") vide circular no. SMD/POLICY/CIR-2/2002 dated January 10, 2002, to implement the SEBI Board decision by suitably amending their Rules, Articles of Association etc., within two months from the date of the said Order; and

Whereas SEBI advised CSE vide letter no. SMD/CSE/ADMN/4536/02 dated March 19, 2002 to confirm whether they had complied with the SEBI directive of January 10, 2002, issued vide SEBI Circular no. 2, whereby no broker member was allowed to hold office as President, Vice-President within a period of two months from the date of the directive and CSE was also advised to confirm whether they had suitably amended the Rules, Articles of Association etc., to give effect to the above decision taken by the SEBI Board and the policy decision of government in this regard; and

Whereas in response to the above mentioned letter and circular dated January 10, 2002, CSE vide its letter dated 19.3.2002 informed that the said directive shall be incorporated after implementation of model rules of conduct and that appropriate changes will be made in the memorandum and articles of association of the exchange after its approval by the committee/SEBI/general body of shareholders, that the process has been initiated and

Whereas most of the stock exchanges have amended their rules/articles of association to give effect to the order of 10.1.2002, and there is failure on the part of CSE to amend the articles of association in the light of the above, SEBI is

of the opinion that in the interests of the investors and the capital markets, as also in public interest, it is necessary and expedient to amend the Articles of Association, in the manner indicated in this Order, inter-alia for the following reasons namely:

- (i) To expedite the corporatisation of stock exchanges by which ownership, management, and trading membership would be segregated from each other to improve institutional mechanism and trading practices in the stock markets.
- (ii) Moreover, the Board finds it desirable to maintain uniformity in the Rules, Regulations and Bye-laws regarding composition of the Governing Board of various stock exchanges in the country.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of Section 8 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with the powers delegated to the Board by the SEBI under its notification no. S.O / 573(E) dated July 3, 1992 issued under Section 29A of the said Act, Securities and Exchange Board of India makes the following amendments to the Articles of Association of CSE namely:-

1. In clause (i) Article 82E,
 - a) the word "elected" appearing after the words "amongst the" and before the word "members" shall be deleted.
 - b) the words "under clause (a) of article 81" appearing after the word "committee" and before the words "within ten days" shall be deleted.
 - c) in the proviso, the word "elected" appearing after the word "no" and before the word "member" shall be deleted.
 - d) after the existing proviso, the following proviso shall be added:

"Provided further that no broker member of the exchange shall be an office bearer i.e. President, Vice President or Treasurer of the exchange."

[F No. SEBI/LE/18591/02]
G. N. BAJPAI, Chairman

